

# GK/GS का





# ECONOMIC SURVEY (आर्थिक सर्वेक्षण)

हमारे TOPIC EXPERT के साथ



देखें शाम 07:00 बजे



**BY GS GURU** 





**Economic** Survey -Introduction The Department of Economic Affairs, Ministry of Finance presents the Economic Survey of India in Parliament every year, just before the Union Budget. This document is submitted to both houses of Parliament during the Budget Session.

वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग हर साल केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में भारत का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करता है। यह दस्तावेज़ बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया

जाता है।

GGZ-5FYR023-24) e Martali Ea Sushung-> 2022-23 e- 31 Jan





**Economic Survey - Introduction** 

- The Economic Survey reviews the developments in the Indian economy over the previous 12 months. It highlights the policy initiatives of the government, summarizes the performance on major development programs, and shows the growth prospects of the economy.
  - आर्थिक सर्वेक्षण पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए विकास की समीक्षा करता है। यह सरकार की नीतिगत पहलों पर प्रकाश डालता है, प्रमुख विकास कार्यक्रमों के प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है और अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाओं को दर्शाता है।



# es/ ek का महासंग्राम

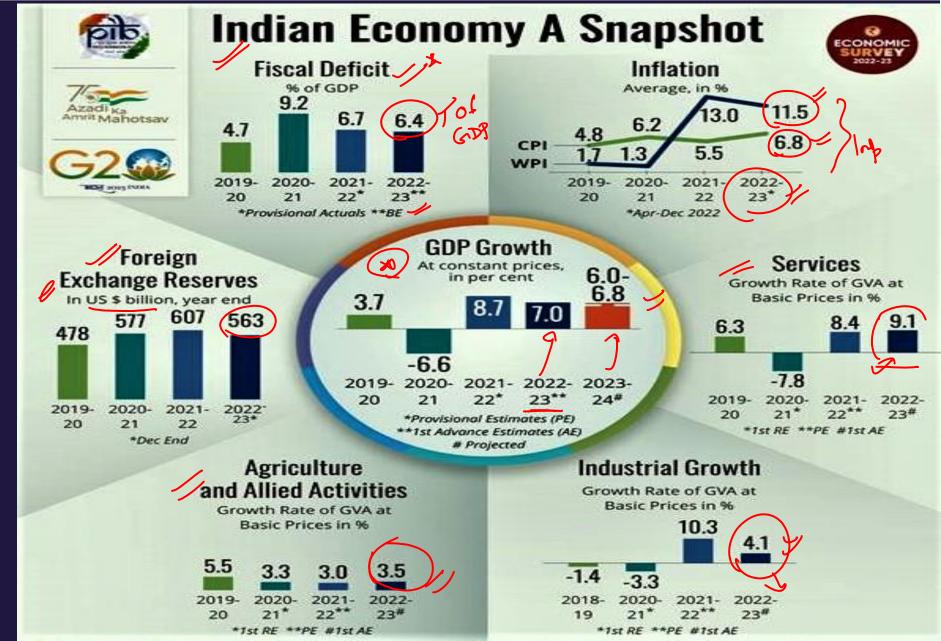


**Economic Survey - Introduction** 

- The Economic Survey 2022-23 prepared by a team of economists led by chief economic adviser Anantha Nageswaran analyses developments in the economy in the past year and makes projections for the following year.
- मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों की एक टीम द्वारा तैयार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पिछले वर्ष में अर्थव्यवस्था में विकास का विश्लेषण करता है और अगले वर्ष के लिए अनुमान लगाता है।











#### Growth

- India is the 3rd largest economy in the world in PPP terms and the 5th largest in market exchange rates.
- GDP The Indian economy is expected to expand 7% in real terms in 2022-23.
- It has been projected to be around 6.0 to 6.8% in 2023-24 depending on the trajectory of economic and political developments globally.
- भारत पीपीपी के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बाजार विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- सकल घरेलू उत्पाद भारतीय अर्थव्यवस्था में 2022-23 में वास्तविक रूप से 7% का विस्तार होने की उम्मीद है।
- वैश्विक स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक विकास के पथ के आधार पर 2023-24 में इसके लगभग 6.0 से 6.8% होने का अनुमान लगाया गया है।





- Global growth is forecasted to slow to 2.7% in 2023 as per IMF's World Economic Outlook, October 2022.
- Private consumption As a percentage of GDP, private consumption recovered to 58.4% in the second quarter of 2022-23, due to rebound in contact-intensive services such as trade and transport.
- आईएमएफ के विश्व आर्थिक आउटलुक, अक्टूबर 2022 के अनुसार 2023 में वैश्विक वृद्धि धीमी होकर 2.7% होने का अनुमान है।
- निजी खपत सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, व्यापार और पिरवहन जैसी संपर्क-गहन सेवाओं में उछाल के कारण, 2022-23 की दूसरी तिमाही में निजी खपत बढ़कर 58.4% हो गई।

#### **Growth**





development s

- Inflation India's retail inflation rate peaked at 7.8% in April 2022, above the Reserve Bank of India's (RBI) upper tolerance limit of 6%.
- Tax collection The gross tax revenue registered a year-on-year growth of 15.5% from April to November 2022 driven by robust growth in the direct taxes and GST.
- Capital expenditure The Centre's capital expenditure rose to 2.5% of GDP in 2021-22.
- मुद्रास्फीति भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2022 में 7.8% पर पहुंच गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6% की ऊपरी सहनशीलता सीमा से ऊपर है।
- कर संग्रह प्रत्यक्ष करों और जीएसटी में मजबूत वृद्धि के कारण अप्रैल से नवंबर 2022 तक सकल कर राजस्व में 15.5% की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की गई।
- पूंजीगत व्यय केंद्र का पूंजीगत व्यय 2021-22 में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% हो गया।





**Monetary management** 

- Non-performing assets The gross non-performing assets ratio of scheduled commercial banks fell to a seven-year low of 5%.
- Fiscal deficit The survey expressed confidence that the Union government should be able to meet the fiscal deficit target of 6.4% of GDP for this financial year.
- The government aims to lower the fiscal deficit to 4.5% of GDP by FY26 from a target of 6.4% of GDP in this fiscal year.
- गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात गिरकर सात साल के निचले स्तर 5% पर आ गया।
  - राजकोषीय घाटा सर्वेक्षण में विश्वास व्यक्त किया गया कि केंद्र सरकार को इस वित्तीय वर्षे के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 6.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए।
  - सरकार का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 6.4% से घटाकर वित्त वर्ष 2016 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% तक लाना है।





Social infrastructur e and employment

- \* Education As a share of total GDP, the budgetary allocation for education was at 2.9%.
- Health The out-of-pocket expenditure as a percentage of total health expenditure declined to 48.2 % in 2018-19. The government aims to lower the fiscal deficit to 4.5% of GDP by FY26 from a target of 6.4% of GDP in this fiscal year.
- शिक्षा कुल सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में, शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन 2.9% था।
- स्वास्थ्य कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में जेब से खर्च 2018-19 में घटकर 48.2% हो गया। सरकार का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 6.4% से घटाकर वित्त वर्ष 2016 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% तक लाना है।





Social infrastructur e and employment

- Food security Schemes like PM-Kisan and PM Garib Kalyan Yojana have helped in ensuring food security and their impact was also endorsed by the United Nations Development Programme (UNDP).
- Inclusion The JAM (Jan-Dhan, Aadhaar and mobile) trinity and direct benefit transfers has brought the marginalised sections into the formal financial system.
  - खाद्य सुरक्षा पीएम-किसान और पीएम गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाओं ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद की है और उनके प्रभाव का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने भी समर्थन किया है।
  - समावेशन JAM (जन-धन, आधार और मोबाइल) त्रिमूर्ति और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ने हाशिए पर रहने वाले वर्गों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में ला दिया है।





Social infrastructur e and employment

- Employment Labour markets recovered beyond pre-Covid levels, in both urban and rural areas, with unemployment rates falling to 4.2% in 2020-21.
- Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) is indirectly creating opportunities for rural households to diversify their sources of income generation.
  - रोजगार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में श्रम बाजार पूर्व-कोविड स्तर से आगे बढ़ गया, 2020-21 में बेरोजगारी दर गिरकर 4.2% हो गई।
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण परिवारों के लिए आय सृजन के स्रोतों में विविधता लाने के अवसर पैदा कर रही है।





# Agriculture and food management

- Private investment Private investment in agriculture rose to 9.3% in 2020-21.
- Institutional credit Institutional credit to the agricultural sector continued to grow to Rs 18.6 lakh crore in 2021-22.
- MSP The minimum support price for all mandated crops was fixed at 1.5 times of the all-India weighted average cost of production from 2018.
- निजी निवेश 2020-21 में कृषि में निजी निवेश बढ़कर 9.3% हो गया।
- संस्थागत ऋण कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण 2021-22 में बढ़कर 18.6 लाख करोड़ रुपये हो गया।
- एमएसपी सभी अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2018 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का 1.5 गुना तय किया गया था।





Agriculture and food management

- \*Foodgrain production Foodgrain production in India saw sustained increase and stood at 315.7 million tonnes in 2021-22.
- India stands at the forefront to promote millets through the International Year of Millets initiative.
- खाद्यान्न उत्पादन भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई और 2021-22 में 315.7 मिलियन टन रहा।
- अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पहल के माध्यम से बाजरा को बढ़ावा देने में भारत सबसे
   आगे है।





#### Industry

- India became the second-largest mobile phone manufacturer globally.
- The production-linked incentive (PLI) schemes were introduced across 14 categories, with an estimated capex of Rs 4 lakh crore over the next five years, to plug India into global supply chains.
- भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया।
  - भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल करने के लिए अगले पांच वर्षों में 4 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित पूंजीगत व्यय के साथ 14 श्रेणियों में उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई।





- The services sector is expected to grow at 9.1% in 2022-23.
- India was among the top ten services exporting countries in 2021.
- India's e-commerce market is projected to grow at 18% annually through 2025.
- 2022-23 में सेवा क्षेत्र के 9.1% की दर से बढ़ने की उम्मीद है।
- भारत 2021 में शीर्ष दस सेवा निर्यातक देशों में से एक था।
- भारत का ई-कॉमर्स बाज़ार 2025 तक सालाना 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है।

#### **Services**





# **External** sector

- Exports Merchandise exports were 332.8 billion dollars for April-December 2022 as India diversified its markets to Brazil, South Africa and Saudi Arabia.
  - India entered into a comprehensive economic partnership agreement with the United Arab Emirates and an economic cooperation and trade agreement with Australia in 2022.
  - निर्यात अप्रैल-दिसंबर 2022 के लिए व्यापारिक निर्यात 332.8 बिलियन डॉलर था क्योंकि भारत ने ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब में अपने बाजारों में विविधता ला दी।
  - भारत ने 2022 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किया।





#### External sector

- Remittances India continued to be the largest recipient of remittances in the world, netting 100 billion dollar in 2022.
- Remittances are the 2nd largest major source of external financing after service exports.
- Forex reserves As of end-November 2022, India was the 6th largest foreign exchange reserves holder in the world.
- ्रिषण भारत दुनिया में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहा, जिसने 2022 में 100 बिलियन डॉलर की कमाई की।
- सेवा निर्यात के बाद प्रेषण बाह्य वित्तपोषण का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। विदेशी मुद्रा भंडार नवंबर 2022 के अंत तक, भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था।





Climate
Change and
Environment

- India declared the Net Zero Pledge to achieve net zero emissions goal by 2070.
- India achieved its target of 40% installed electric capacity from non-fossil fuels ahead of 2030.
- भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शुद्ध शून्य प्रतिज्ञा की घोषणा की।
- भारत ने 2030 से पहले गैर-जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया।





Climate
Change and
Environment

- A mass movement LIFE— Life style for Environment was launched.
- Sovereign Green Bond Framework (SGrBs) were issued in 2022.
- National Green Hydrogen Mission enables India to be energy independent by 2047.
- पर्यावरण के लिए एक जन आंदोलन लाइफ-लाइफ स्टाइल शुरू किया गया।
- सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क (एसजीआरबी) 2022 में जारी किए गए थे।
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत को 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने में सक्षम बनाता है।





Infrastructu re Physical Infrastructure- Projects that are currently active include:

- National Infrastructure Pipeline
- National Monetisation Pipeline
- Gati Shakti
  - National Logistics Policy

भौतिक अवसंरचना- वर्तमान में सक्रिय परियोजनाओं में शामिल हैं:

- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन
- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन
- गति शक्ति
- राष्ट्रीय रसद नीति





# Infrastructu re

#### Digital Public Infrastructure

- Unified Payment Interface (UPI)-based transactions grew in value (121%) and volume (115%) terms between 2019-22.
- Rural internet subscriptions witnessed a 200% increase, between 2015 and 2021.

#### डिजिटल सार्वजिनक अवसंरचना

- एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI)-आधारित लेनदेन 2019-22 के बीच मूल्य (121%) और मात्रा (115%) के संदर्भ में बढ़े।
- 2015 और 2021 के बीच ग्रामीण इंटरनेट सदस्यता में 200% की वृद्धि देखी गई।





# Infrastructu re

#### Digital Public Infrastructure

- Unified Payment Interface (UPI)-based transactions grew in value (121%) and volume (115%) terms between 2019-22.
- Rural internet subscriptions witnessed a 200% increase, between 2015 and 2021.

#### डिजिटल सार्वजिनक अवसंरचना

- एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI)-आधारित लेनदेन 2019-22 के बीच मूल्य (121%) और मात्रा (115%) के संदर्भ में बढ़े।
- 2015 और 2021 के बीच ग्रामीण इंटरनेट सदस्यता में 200% की वृद्धि देखी गई।





Q.1 Who prepares the Economic Survey? आर्थिक सर्वेक्षण कौन तैयार करता है? Lilu/garyfusoilo



- A. Principal Economic Advisor and other officials
- B. Chief Economic Advisor
- C. Ministry of Economic Affairs
- D. None of the above





Q.2 When was the first Economic Survey presented in India?







Q.3 When is Economic Survey presented in the Parliament? आर्थिक सर्वेक्षण संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है?



Eco-Survey Dates.

A. A working day before the Budget

B. A working day after the Budget

C. A week before the Budget

D. A month after the Budget



## es/ ek का महासंग्राम



- Since Independence, the Economic Survey was presented alongside the Budget, but was delinked in 1964 and was presented in advance, a practice that continues to date. The Economic Survey 2023 was presented on 31 January 2023 by Finance Minister Nirmala Sitharaman.
- आज़ादी के बाद से, आर्थिक सर्वेक्षण बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 1964 में इसे अलग कर दिया गया और पहले ही प्रस्तुत किया गया, यह प्रथा आज भी जारी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 31 जनवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया था।





Q. 4 According to Economic Survey 2022-23, what is real terms economic growth in

/ 2022-23?

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, 2022-23 में वास्तविक आर्थिक वृद्धि क्या है?



(a) 6 Percent

(b) 6.5 Percent

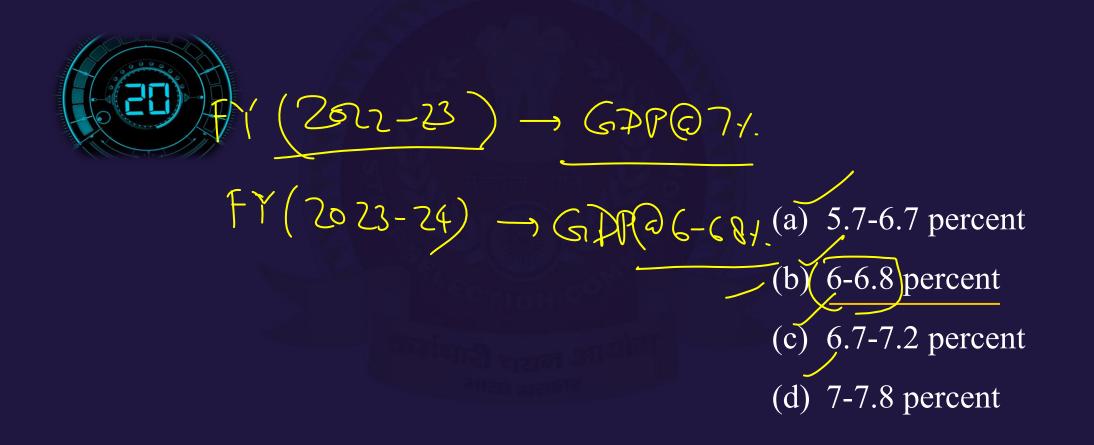
(c) 7 Percent

(d) 7.5 Percent





Q.5 What is expected range India's of GDP in 2023-24 (economic survey 2022-23)? 2023-24 (आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23) में भारत की जीडीपी की अपेक्षित सीमा क्या है?







Q.6 Under Economic survey 2022-23, what is expected fiscal deficit in 2023-24? आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के तहत 2023-24 में कितना राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है?



(a) 5.4 Percent

(b) 6.4 Percent

(c) 7.4 Percent

(d) 7.7 Percent





Q.7 Who prepared economic survey? आर्थिक सर्वेक्षण किसने तैयार किया?



- a) Department of Economic Affairs
- b) Finance Commission
- c) RBI
- d) Public Account Committee





- Economic Survey annually prepared by Economic Division of the Department of Economic Affairs (DEA), Ministry of Finance.
- Under the guidance of the Chief Economic Advisor (CEA).
- वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के आर्थिक प्रभाग द्वारा प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है।
- मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) के मार्गदर्शन में।



#### es/ ek का महासंग्राम



Q.8 Which has first declared Swachh, Sujal Pradesh?

स्वच्छ, सुजल प्रदेश की घोषणा सबसे पहले किसने की?



- a) Andaman & Nicobar Islands
- b) Lakshadweep Islands
- c) Puducherry
- d) Chandigarh





- Andaman & Nicobar Islands is now the first Swachh, Sujal Pradesh because all of its villages have been declared as ODF plus models.
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अब पहला स्वच्छ, सुजल प्रदेश है क्योंकि इसके सभी गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित किया गया है।





Q.9 JALDOOT App related to \_\_\_\_\_.

जलदूत ऐप\_\_\_ से संबंधित है।





- a) Provide warning against flood
- b) Provide warning against flood at coastal zones
- c) Provide information for flood intensity
  - d) Provide information for wells water level





Q.10 India declared the Net Zero Pledge to achieve a net zero emissions goal by: भारत ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शुद्ध शून्य प्रतिज्ञा की घोषणा की:



- a) 2045
- b) 2050
- c) 2060
- d) 2070





Q.11 Which sector is highest FDI Equity Inflows during April-September 2022? अप्रैल-सितंबर 2022 के दौरान किस क्षेत्र में सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह है?



- a) Service
- b) Software and Hardware
- c) Trading
- d) Automobiles